

**न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभाग, कोटा**  
(निर्णय बईजलास श्री के0 सी0 वर्मा आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 29/2017ग्र/अपील/आर्म्स/बूंदी  
दायरा दिनांक 22.5.2017  
किरम अपील: धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

**उनवान**

गेमालाल पुत्र रूपा जाति बंजारा निवासी बडफू थाना डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी।

....अपीलार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी।

....रेस्पोडेन्ट



उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी  
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

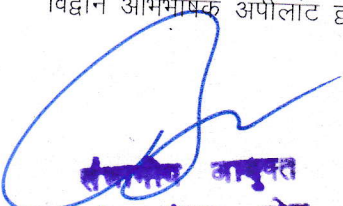
दिनांक 6.8.2018

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश संख्या 70 दिनांक 17.4.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

- 1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 819/ADM/City/87 जिला मजिस्ट्रेट कोटा से स्वीकृत है जो जिला मजि0 बूंदी के यहां 143/OUT/BND/14 पर दर्ज है को नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट ली गई जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ने अपनी रिपोर्ट DSB/BUNDI/A -(10) ARM.RIN (R)/16/9781 दिनांक 31.12.2016 मे प्रार्थी के विरुद्ध (1) प्रकरण सं0 42/99 धारा 379 आईपीसी व 41, 42 फोरेस्ट एक्ट मे दर्ज हुवा जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा बरी किया गया (2) प्रकरण सं0 117/08 धारा 323, 324, 341 आईपीसी मे दर्ज हुवा जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। (3) प्रकरण संख्या 428/08 धारा 419, 120 बी, 467, 410, 471 आईपीसी का माननीय न्यायालय मे विचाराधीन होने से अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध 3 प्रकरण दर्ज से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी के विरुद्ध तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 819/ADM/City/87 जिला मजिस्ट्रेट कोटा जो जिला मजि0 बूंदी के यहां 143/OUT/BND/14 पर दर्ज है को आदेश संख्या 70 दिनांक 17.4.2017 से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर धारित शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं0 10280 को अविलम्ब थाना डाबी मे जमा कराने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश

**अधीक्षक**  
**कोटा सभाग, कोटा**

- से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय के पेश की गई थी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी का आदेश विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। पुलिस अधीक्षक बून्दी कि रिपोर्ट में चाल चलन अच्छा होना तथा प्रकरण संख्या 42/92 में बरी प्रकरण संख्या 117/08 में निर्णय दिनांक 30.04.2013 को 200/-रूपये जुर्माने का अर्थदण्ड व तीसरा प्रकरण 428/2008 विचाराधीन होना वर्णित किया है। रिपोर्ट में शस्त्र के दुरुपयोग से संबंधी कोई आरोप नहीं है। अपीलान्त के विरुद्ध अदावतन झूठे प्रकरण दर्ज होने के आधार पर अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं करना उचित नहीं है। अपीलांत वर्ष 1988 से शस्त्र का नवीनीकरण कराता रहा है। अपीलान्त को अपनी जान माल की रक्षा के शस्त्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी का आदेश दिनांक 17.04.2017 निरस्त किया जाकर नियमानुसार दिनांक 31.12.2016 से आगामी अवधि के लिये शस्त्र नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।xx
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पों राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx
  - 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि जेरअपील आदेश विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है क्योंकि पुलिस अधीक्षक बून्दी कि रिपोर्ट में चाल चलन अच्छा होना तथा प्रकरण संख्या 42/92 में बरी प्रकरण संख्या 117/08 में निर्णय दिनांक 30.04.2013 को 200/- रूपये जुर्माने का अर्थदण्ड व तीसरा प्रकरण 428/2008 विचाराधीन होना वर्णित किया है। शस्त्र के दुरुपयोग से संबंधी कोई मामला नहीं है। अपीलान्त के विरुद्ध अदावतन झूठे प्रकरण दर्ज होने के आधार पर अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं करना उचित नहीं है क्योंकि अपीलांत वर्ष 1988 से शस्त्र का नवीनीकरण कराता रहा है। ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर नियमानुसार आगामी अवधि के लिये लाईसेन्स नवीनीकरण की आज्ञा प्रदान की जावे। अपने तर्क के समर्थन मे 2016 (4) डब्लू एल एन(राज0) पेज 425 ता 427 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। xx
  - 4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पों ने अपनी बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक बून्दी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध गम्भीर आपराधिक धाराओं मे 3 प्रकरण दर्ज हुये है एक प्रकरण मे बरी व दुसरे प्रकरण मे अर्थ दण्ड से दण्डित किया है तथा तीसरा प्रकरण वर्तमान मे न्यायालय मे विचाराधीन है जिसको स्वयं अपीलार्थी ने भी स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक बून्दी द्वारा नवीनीकरण करने की अनुशंषा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील आदेश से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नहीं है। अपील खारिज की जावे। xx
  - 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रकरण विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2016 (4) डब्लू एल एन(राज0) पेज 425 ता 427 पर

  
 राजकीय अभिभाषक  
 जेज संभाग, कोटा

गौर कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंट राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं० 143/OUT/BND/14 दिनांक 31.12.2016 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा नवीनीकरण किया गया है। अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट DSB/BUNDI/A -(10) ARM.RIN (R)/16/9781 दिनांक 31.12.2016 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध (1) प्रकरण सं० 42/99 धारा 379 आईपीसी व 41, 42 फोरेस्ट एक्ट में दर्ज हुआ जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा बरी किया गया (2) प्रकरण सं० 117/08 धारा 323, 324, 341 आईपीसी में दर्ज हुआ जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। (3) प्रकरण संख्या 428/08 धारा 419, 120 बी, 467, 410, 471 आईपीसी का माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील आदेश दिनांक 17.4.2017 से अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि वर्ष 1988 से अपीलांत का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाता रहा है शस्त्र के दुरुपयोग से संबंधित कोई मामला पुलिस रिपोर्ट में वर्णित नहीं है ऐसी स्थिति में अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं करना उचित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र अंतिम बार दि० 5.12.2014 को दिनांक 31.12.2016 तक की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया है अंतिम बार नवीनीकरण करते समय उक्त आपराधिक रिकार्ड पर विचार किया उक्त तीनों प्रकरण काफी पुराने हैं जिसमें से एक प्रकरण में अपीलांत बरी एवं दूसरे में अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा तीसरा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। शस्त्र के दुरुपयोग से संबंधित कोई मामला नहीं है तथा ना ही अन्य ऐसे कोई तथ्य/आधार अभिलेख पत्रावली में मौजूद है जो शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण में बाधक हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र जेरअपील आदेश संख्या 70 दिनांक 17.4.2017 से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजि० बूंदी द्वारा पारित आदेश सं० 70 दिनांक 17.4.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पर नये सिरे से विचार कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है। xx

- 6 निर्णय आज दिनांक 6.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के० सी० वर्मा )

सहाय्यीय आयुक्त

कोटा

कोटा, राजपूताना, कोटा